घुसपैठियों के लिए बंगाल के सभी जिलों में बनाए जाएंगे हिरासत केंद्र

अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं की घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल सरकार का अहम आदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। हाल में घुसपैठियों के खिलाफ धर-पकड़ अभियान व पुशबैक नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने अब राज्य के सभी जिलों में 'होल्डिंग सेंटर' (हिरासत केंद्र) बनाने का निर्देश दिया है। इन सेंटरों में उन लोगों को रखा जाएगा, जिन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या होने के शक में हिरासत में लिया गया है या जिन्हें आगे पकड़ा जाएगा। देश से बाहर भेजने से पहले इन होल्डिंग सेंटरों में संदिग्धों को 30 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा।

राज्य के गृह विभाग ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर होल्डिंग सेंटर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो मई, 2025 के पत्र का भी जिक्र है, जिसमें देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़े गए बांग्लादेशियों/रोहिंग्याओं के देश-निकाला के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पत्र में कहा गया है कि इन हिरासत केंद्रों का प्रयोग सिर्फ उन लोगों के लिए ही नहीं किया जाएगा, जिन्हें हाल ही में घुसपैठिया होने के शक में हिरासत में लिया गया है, बल्कि उनके लिए भी किया जा सकता है जिन्हें पहले ही पकड़ा जा चुका है, जो जेल में हैं।

घुसपैठियों पर सख्ती

- राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को हिरासत केंद्र बनाने का दिया निर्देश
- डीजीपी सहित सभी पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी गई आदेश कीप्रतियां

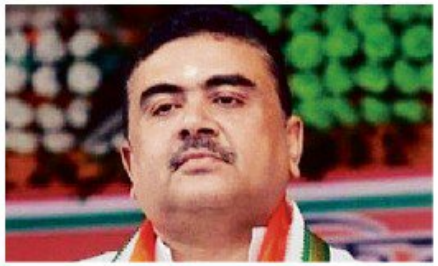

शुभेंदु अधिकारी। फाइल

इस कदम का उद्देश्य, हिरासत व वापसी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

आदेश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक सहित राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों, आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और कोलकाता में विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को भी भेजी गई है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हिरासत और वापसी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए कहा गया है ताकि देश-निकाला का इंतजार कर रहे अवैध विदेशी नागरिकों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक नियंत्रित तरीके से रखा जा सके। इसके बाद बीएसएफ व अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश और रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सीधे बीएसएफ को सौंपे जाएंगे घुसपैठिए

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीते बुधवार को बीएसएफ महानिदेशक प्रवीण कुमार की मौजूदगी में राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य में घुसपैठियों की धर-पकड़ अभियान व पुशबैक नीति तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा की थी। कहा था कि इसके तहत जो लोग नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के दायरे में नहीं आते, उनकी पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस घुसपैठियों को कोर्ट में पेश करने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपेगी। बीएसएफ घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट (निर्वासित) करने की कार्रवाई करेगी। यह प्रक्रिया डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के सूत्र पर चलाई जाएगी।

'डबल इंजन' की रफ्तार से बदलते बंगाल की नई तस्वीर पेज>>4

भारत-अमेरिका रिश्तों में दिखी गर्मजोशी, जल्द होगी ट्रेड डील

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभदायक और टिकाऊ होगा
- भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में ग्रीन कार्ड समेत भारत की कई आपत्तियों पर रखा अपना पक्ष

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने अमेरीकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ। एएनआइ

भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की नई दिल्ली में रविवार को हुई बहुप्रतीक्षित बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के मौजूदा अवरोधों को समाप्त करने व एक दूसरे के प्रति भरोसे को और मजबूत करने को लेकर अहम विमर्श हुआ। ट्रंप टैरिफ के बाद आए तनाव के बाद रिश्तों में अब गर्मजोशी दिखी है। चार दिनी यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा,दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम देने के करीब हैं। जल्द ही समझौता हो सकता है। यह दोनों के लिए लाभदायक, व टिकाऊ होगा और आपसी हितों को आगे बढ़ाएगा। जयशंकर ने ग्रीन कार्ड समेत अमेरिकी वीजा और आव्रजन के नियमों में उन बदलावों की तरफ ध्यान दिलाया जिसके सबसे ज्यादा शिकार भारतीय पेशेवरों व भारतीय उद्योग जगत को होने की आशंका है। जयशंकर ने कहा, इस नए दृष्टिकोण से विधि सम्मत आवाजाही पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।

रूबियो-जयशंकर के बीच बैठक में मुख्य जोर व्यापार, अहम खनिजों, ऊर्जा, सीमा पार आतंकवाद व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने पर था। प्रेट्र के अनुसार,संयुक्त प्रेस वार्ता में रूबियो ने कहा, हमारे व्यापार प्रतिनिधि जल्द यहां आएंगे। हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में था। हमने जबरदस्त प्रगति की है।' जयशंकर ने कहा, 'हमने आपसी, परस्पर लाभकारी व्यापार से जुड़े अंतरिम समझौते के अंतिम मसौदे को जल्द पूरा करने के महत्व पर बात की है। यह व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में अहम कदम होगा।' रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के प्रति अमेरिका के समग्र दृष्टिकोण को पुनः संतुलित करना है, न कि किसी विशेष देश को निशाना बनाना। हम विश्व में ऐसे समझौते करना चाहते हैं, जो अमेरिका और व्यापारिक साझीदारों के लिए अच्छे हों। रूबियो ने भारत को विशाल अर्थव्यवस्था व अमेरिका का प्रमुख व्यापारिक साझीदार बताया। भारत ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से कई बार भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाने का मुद्दा भी उठाया। जागरण ब्यूरो के अनुसार, रूबियो ने स्वीकारा,अमेरिका अपनी आव्रजन नीतियो में सुधार कर रहा है जिससे तत्कालिक परेशानी हो सकती है। इस प्रक्रिया का निशाना भारत नहीं है। अमेरिका में प्रवासन संकट रहा है, पर यह भारत के कारण नहीं है। जयशंकर ने कहा, 'भारत अवैध आवाजाही से निपटने में सहयोग करता है,पर अपेक्षा है कि इससे कानूनी आवाजाही पर प्रतिकूल असर न पड़े।

जयशंकर ने बताया, भारत के लिए क्यों जरूरी हैं ऊर्जा के कई स्रोत पेज>>3

भारतीयों पर नस्ली टिप्पणियों पर बोले रूबियो- हर देश में होते हैं मूर्ख

जागरण ब्यूरो के अनुसार, अमेरिका में भारतीयों के विरुद्ध नस्ली टिप्पणियों के बारे में रूबियो ने कहा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आनलाइन या अन्य जगहों पर ऐसी टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में मूर्ख होते हैं।; अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो हर समय मूर्खता भरी टिप्पणियां करते रहते हैं।" कहा, "हमारा देश उन लोगों से समृद्ध हुआ है जो दुनियाभर से हमारे देश में आए, अमेरिकी बन गए, हमारी जीवनशैली में घुलमिल गए और देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया।

जयशंकर ने पांच बिंदुओं के जरिये बताया भारत का रुख

- हम संघर्षों को सुलझाने के लिए बातचीत व कूटनीति का समर्थन करते हैं।
- हम सुरक्षित व निर्बाध समुद्री व्यापार का समर्थन करते हैं।
- हम अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन की मांग करते हैं।
- हम बाजार हिस्सेदारी व संसाधनों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के विरुद्ध हैं।
- हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम-मुक्त बनाने के लिए भरोसेमंद साझेदारियों व मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के महत्व में विश्वास रखते हैं।

उच्च संवर्धित यूरेनियम छोड़ने पर सिद्धांतत : तैयार ईरान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

व्यापक समझौते पर बातचीत के लिए शुरुआती तौर पर 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसी दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भविष्य जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संभावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता शामिल हो सकती है। साथ ही अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के निपटान पर भी सहमति बनने के संकेत हैं।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ईरान ने अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को छोड़ने पर सिद्धांततः सहमति दे दी है, भले ही वह सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार न करे। संभावना है कि यूरेनियम की कुछ मात्रा को हल्का किया जाएगा, जबकि शेष को किसी तीसरे देश, संभवतः रूस को हस्तांतरित किया जाएगा। बता दें कि 2015 में ओबामा प्रशासन के साथ हुए समझौते के तहत ईरान ने उस समय के अपने यूरेनियम भंडार का लगभग 97% हिस्सा रूस भेज दिया था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के अनुसार, ईरान के पास 60 प्रतिशत तक संवर्धित 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जिसे हथियार-ग्रेड स्तर तक पहुंचाने के लिए बहुत कम अतिरिक्त तकनीकी प्रक्रिया की जरूरत होगी। सूत्रों के मुताबिक, समझौते के तहत अमेरिका ईरान के विदेशों में फ्रीज फंड जारी करने और तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को धीरे-धीरे सामान्य करेगा। हालांकि, तेहरान ने इसे अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के पालन से जोड़ा है।

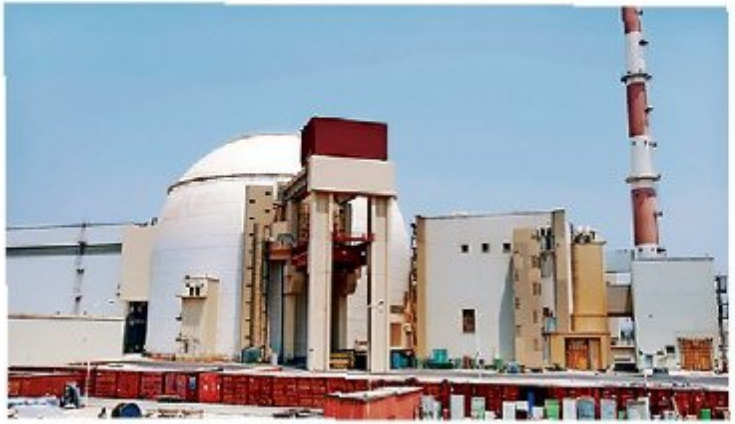

यूरेनियम की कुछ मात्रा को हल्का किया जाएगा

<< तेहरान से 1,200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बुशेहर परमाणु रिएक्टर।

इंटरनेट मीडिया

सोमवार को बाजार में उछाल संभव

ऊर्जा बाजार इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। दुनिया की लगभग एक-पांचवीं तेल आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरती है। ऐसे में तनाव कम होने की खबरों को बाजार के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अबू धाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी के प्रमुख का कहना है कि पूरी तरह सामान्य स्थिति 2027 से पहले लौटना मुश्किल हो सकता है।

इन सवालों के जवाब अब भी बाकी

- क्या समझौता केवल होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक आवाजाही बहाल करने तक सीमित है, या ईरान भविष्य में भी इस मार्ग पर नियंत्रण का दावा करेगा?
- क्या होर्मुज से जहाजों की आवाजाही स्थायी रूप से सामान्य होगी, या ईरान "टोल" और निगरानी का अधिकार अपने पास रखेगा?
- क्या अमेरिका ईरान की मांग के अनुसार विदेशों में फ्रीज 25 अरब डालर की राशि जारी करेगा?
- क्या ईरान लगभग बम-ग्रेड स्तर तक संवर्धित यूरेनियम को तीसरे देश को सौंपेगा या उसे कम संवर्धित स्तर पर लाएगा?
- अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के अनुसार ईरान के पास मौजूद करीब 11 टन अन्य संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा?
- क्या ईरान को भविष्य में यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की अनुमति मिलेगी?
- क्या ईरान 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर सहमत होगा, जैसा संकेत राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके हैं।

उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर देश में सर्वाधिक

हेमंत श्रीवास्तव ● जागरण

- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में मातृ मृत्यु दर 141 से बढ़कर हुई 154
- राज्य परिवर्तन आयोग ने वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करने का दिया निर्देश

लखनऊः मातृ और शिशु कल्याण की दिशा में लगातार प्रयास से भारत ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने में न केवल बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन, उत्तर प्रदेश में इस प्रयास को बड़ा झटका लगा है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कराए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) सर्वे की नवीनतम रिपोर्ट में प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटने की जगह बढ़ गया है। यह एक वर्ष में 141 से बढ़कर 154 हो गया है। यह देश में सर्वाधिक है।

राज्य परिवर्तन आयोग (एसटीसी) ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष को मृत्यु दर पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। एसटीसी के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने 20 मई को प्रकाशित एसआरएस की रिपोर्ट के हवाले से इस पर चिंता व्यक्त की है।

शीर्ष के पांच राज्य

उत्तर प्रदेश	154
मध्य प्रदेश	135
छत्तीसगढ़	124
ओडिशा	124
उत्तराखंड	99

नीचे के पांच राज्य

केरलम	24
तमिलनाडु	25
महाराष्ट्र	37
आंध्र प्रदेश	39
तेलंगाना	48

* मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख पर

मातृ मृत्यु दर

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) से आशय गर्भावस्था, प्रसव के दौरान या उसके बाद के 42 दिनों के अंदर माताओं की होने वाली मृत्यु की गणना प्रति एक लाख स्वस्थ जन्मे बच्चों के अनुपात में की जाती है।

केंद्र सरकार ने तय समय से पहले ही इस दर को 100 से कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। वर्तमान में एक लाख जीवित जन्मों पर एमएमआर का राष्ट्रीय अनुपात 88 है। एमएमआर में समय पूर्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लिए पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा भी हुई है।

यूपी सरकार का रोडमैप तैयार पेज>>3

मंडे मेगा स्टोरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया

इबोला पर भारत का अलर्ट- कांगो, युगांडा, सूडान की यात्रा टालें; लौटने पर लक्षण दिखें तो बताएं

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली/ विजयवाड़ा

अफ्रीका के कांगो और युगांडा में इबोला वायरस फैलने के बाद भारत सरकार ने कांगो (डीआरसी), युगांडा और दक्षिण सूडान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। केंद्र ने भारतीयों से इन 3 देशों की गैरजरूरी यात्रा टालने को कहा है। इन देशों से लौटे या वहां से ट्रांजिट कर भारत आए यात्रियों को 21 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी। बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, गले में खराश, ब्लीडिंग जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत एयरपोर्ट हेल्थ डेस्क या डॉक्टर को बताना होगा। इमिग्रेशन से पहले हेल्थ आफिसर को सूचना देने और पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बताने को भी कहा गया है।

भारत में अभी इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का कोई केस नहीं मिला है। केरल और कर्नाटक के बाद अब आंध्र प्रदेश ने भी एयरपोर्ट निगरानी शुरू की है। विशाखापत्तनम, तिरुपति और विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्क्रीनिंग होगी। लक्षण मिलने पर यात्री को क्वारंटीन किया जाएगा। एयरपोर्ट वाले शहरों के अस्पतालों में 15-15 बेड के आइसोलेशन वार्ड तैयार रखे गए हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में कुल 58,560 भारतीय मूल के लोग रहते हैं।

कांगो में 20 दिनों में 200 मौतें: बाजार में खत्म हुए सैनिटाइजर, मास्क की कीमत 10 गुना बढ़ी

• The New York Times
दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

किन्शासा | डीआरसी कांगो के इतुरी प्रांत की राजधानी बुनिया में इबोला अब सिर्फ बीमारी नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का डर बन गया है। 5 मई को इसी इलाके से अज्ञात बीमारी का पहला अलर्ट आया था। अब 20 दिनों में संदिग्ध केस 867 और मौतें 204 तक पहुंच गई हैं।

बुनिया शहर में सैनिटाइजर और डिसइन्फेक्टेंट की किल्लत है। जो सैनिटाइजर पहले 2,500 कांगोली फ्रैंक, करीब 85 रुपए में मिलता था, वह अब चार गुना महंगा होकर करीब 10,000 फ्रैंक यानी 340 रुपए तक बिक रहा है। मास्क मिलना मुश्किल है और स्थानीय रिपोर्ट्स में इनके दाम 10 गुना तक बढ़ने की बात कही गई है। अस्पतालों की हालत भी दबाव में है। मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिकल मदद कम है। विशेषज्ञों की चिंता है कि यहां से 600 किमी दूर स्थित 2 करोड़ की आबादी वाली राजधानी किन्शासा तक वायरस पहुंचा तो संकट कई गुना बढ़ सकता है।

कांगो में इबोला फैलने के बाद पड़ोसी देशों ने सतर्कता बढ़ा दी है। युगांडा ने कार्यक्रम और कांगो-युगांडा सार्वजनिक परिवहन रोका। रवांडा ने विदेशी यात्रियों की एंट्री रोक दी है। जाम्बिया-मलावी ने एयरपोर्ट व बॉर्डर स्क्रीनिंग बढ़ाई।

दुनियाभर में तैयारियां शुरू

अमेरिका: ट्रैवल हिस्ट्री पर स्क्रीनिंग
अमेरिका ने कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान से 21 दिन में लौटे यात्रियों पर एंट्री रिस्ट्रिक्शन और बढ़ी हुई स्क्रीनिंग लागू की। अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड होल्डर भी जांच से गुजरेंगे। ऐसी फ्लाइट्स को तय एयरपोर्ट पर लाने का निर्देश है, ताकि पब्लिक हेल्थ स्क्रीनिंग हो सके।

चीन: 6 महीने का कस्टम्स अलर्ट
चीन ने 18 मई से 6 महीने का कस्टम्स अलर्ट लागू किया। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को लक्षण खुद बताने होंगे। संदिग्ध ट्रांसपोर्ट, कंटेनर, लगेज, पार्सल पर सैनिटरी ट्रीटमेंट होगा।

जापान: लेवल-1 ट्रैवल रिस्क अलर्ट
जापान ने कांगो और युगांडा के लिए इन्फेक्शियस डिजीज रिस्क लेवल-1 जारी किया। रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल रजिस्ट्रेशन की सलाह दी गई।

फ्रांस: मायोट में एयरपोर्ट निगरानी
फ्रांस ने मायोट में इबोला निगरानी और रोकथाम की मजबूत तैयारी की है। अफ्रीका से समुद्री संपर्क के कारण मायोट संवेदनशील है। एयरपोर्ट-पोर्ट सर्विलांस, संदिग्ध की पहचान और अस्पतालों में आइसोलेशन-रिस्पॉन्स व्यवस्था मजबूत की गई।

गोण्डा से गोल्डनगंज तक बनेगी तीसरी व चौथी लाइन बिछेगी

देश के दो राज्यों को जोड़ेगा 378 किमी लंबा रेल कॉरिडोर

भास्कर न्यूज | छपरा

उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच रेल यातायात को एक नई रफ्तार देने के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक पर काम तेज कर दिया है। गोण्डा कचहरी से गोल्डनगंज तक प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को लेकर शनिवार को सारण के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहर्ता कक्ष में हाई-लेवल बैठक हुई। इस अंतरप्रांतीय रेल परियोजना की प्रारंभिक रूपरेखा पर वरिष्ठ रेल अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच बेहद गहन और रणनीतिक विमर्श हुआ। यह परियोजना पूर्वांचल और उत्तर बिहार के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदलने वाली साबित होगी।

बैठक में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साझा किए गए प्रारंभिक खाके के अनुसार, यह विशाल बुनियादी ढांचा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 378.742 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस परियोजना के दायरे में उत्तर प्रदेश के 5 जिले और बिहार के 2 जिले (सीवान एवं सारण) आएंगे। विशेष बात यह है कि इस पूरे रूट का 49 किलोमीटर का हिस्सा अकेले सारण जिले के अंतर्गत पड़ेगा, जो जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

सारण के डीएम ने रेलवे संग बनाई महायोजना

लोगों को सीधा फायदा होगा

समीक्षा के दौरान यह महत्वपूर्ण बात सामने आई कि चैनवा से गोल्डनगंज तक रेलवे की मौजूदा लाइन और उससे सटे क्षेत्रों के विस्तारीकरण के लिए नए सिरे से भू-अर्जन करने की आवश्यकता होगी। इस बाईपास के बनने से ट्रेनों के परिचालन में समय की भारी बचत होगी और आबादी वाले क्षेत्रों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा।

मेगा प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर

इस नए रेल खंड को पूरी तरह सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान डिजाइन के अनुसार, सारण जिले के भीतर ही इस ट्रैक पर निम्नलिखित संरचनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

- रोड अंडर ब्रिज : 16 (ताकि, स्थानीय यातायात प्रभावित न हो)।
- बड़े पुल : 14 (नदियों और बड़े जलस्रोतों के ऊपर)
- छोटे पुल : 93 (नहरों व नालों के ऊपर)
- रेल ओवर रेल : 01 (तकनीकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण संरचना), चैनवा से गोल्डनगंज तक होगा नया भू-अर्जन, कोपा से बनेगा स्पेशल बाईपास।

सभी विभाग करें संयुक्त सर्वे, रुकावटें करें दूर : डीएम

परियोजना की महत्ता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और तकनीकी विभागों को निर्देश दिया है कि वे रेलवे के साथ मिलकर पूरे रूट का संयुक्त भौतिक सत्यापन करें। डीएम ने कहा कि यह देश की बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है। एनएचएआई, जल संसाधन, पथ निर्माण, विद्युत और लघु सिंचाई विभाग के अभियंता तुरंत रेलवे अधिकारियों के साथ फील्ड में उतरें। संयुक्त सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नया रेलवे ट्रैक बनने से हमारे नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों, बिजली की लाइनों या सिंचाई नहरों के संचालन में कोई बाधा न आए। सभी संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट त्वरित गति से जिला प्रशासन को सौंपने का आदेश दिया गया है।

Rubio, Jaishankar stress need for 'unimpeded' maritime trade

'Tactical' relations the U.S. has with other countries will not come at the 'expense' of strategic alliance with India, says U.S. Secretary of State Marco Rubio; Trump speaks over the phone at an event, says India can 100% count on the U.S. President

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

The United States works with many countries at a "tactical" level, but those relations will not disturb the strategic partnership with India, U.S. Secretary of State Marco Rubio said here on Sunday.

Addressing a joint press conference at the Hyderabad House lawns, Mr. Rubio said the idea of a "free and open Indo-Pacific" went beyond the Indo-Pacific to other "international waters" and accused Iran of blocking the Strait of Hormuz while sponsoring proxy terror groups.

Speaking on the occasion, External Affairs Minister S. Jaishankar acknowledged the disruption to supply chains because of the U.S.-Israel war on Iran, and said that both India and the U.S. had "very strong interest" to ensure "safe and unimpeded maritime commerce".

"As far as our relations with other countries, yeah, we have relations and we work at the tactical level, for example, and in many other ways with countries all over the world. So does India. That's what responsible nation states do but I don't view our relation with any country in the world as coming at the expense of our strategic alliance with India...," Mr. Rubio said. He was responding to a question on the Pakistan-U.S. ties that are being discussed worldwide because of the prominent role that Pakistan has been playing in bringing the conflict in the Gulf to a pause.

Pivotal talks: External Affairs Minister S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio addressing the press at Hyderabad House in New Delhi after their meeting on Sunday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Mr. Rubio, who arrived in India for a four-day visit on Saturday, held a day-long meeting with Mr. Jaishankar and other officials of the Indian side including Foreign Secretary Vikram Misri, in which energy, bilateral trade, and visa issues for skilled Indian workers were among the items discussed.

Trump speaks

Later on Sunday night, U.S. President Donald Trump called Prime Minister Narendra Modi a "great friend" and said India can "count on me 100%". In a telephone call with U.S. Ambassador Sergio Gor, which was played out loud during an event at the Bharat Mandapam celebrating 250 years of U.S. independence, where both Mr. Jaishankar and Mr. Rubio were present, Mr. Trump said the U.S. was closer to India than ever. "I love the Prime Minister.. I am a big fan [of Mr. Modi]... we have never been closer to India and India can count on me 100% and our country. If they [India] ever need help, they know where to call," Mr. Trump said.

CONTINUED ON
» PAGE 10

Congress targets Modi over Rubio's trade claim

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Targeting Prime Minister Narendra Modi over U.S. Secretary of State Marco Rubio's statement that India has committed to purchasing $500 billion worth of American goods over the next five years, the Congress on Sunday alleged that the "compromised PM" was going the extra mile to appease his "good friend".

Congress leader Jairam Ramesh questioned why key announcements relating to India's foreign policy and bilateral engagements were emanating from Washington rather than New Delhi. Noting that India's annual imports from the U.S. stood at $52.9 billion, he said this would have to be doubled to honour the commitment claimed by Mr. Rubio.

CONTINUED ON
» PAGE 10

Quad grouping is 'vital', says Japan's Foreign Minister

Suhasini Haidar
NEW DELHI

Responding to concerns that the Quad has lost its relevance, Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi has said that the four-nation grouping remains a "vital framework". In a written interview with *The Hindu* ahead of the Quadrilateral Foreign Ministers' Meeting in New Delhi on Tuesday, Mr. Motegi indicated that "cooperation over critical minerals" needed for green energy and high technology would be at the top of the meeting agenda.

Japan is working on critical minerals' projects in India, he said while calling for improved infrastructure, more tax subsidies, and protection for intellectual property rights.

The Quad meeting, which will see External Affairs Minister S. Jaishankar host Mr. Motegi, U.S. Secretary of State Marco Rubio, and Australian Foreign Minister Penny Wong, is expected to take stock of the conflict in West Asia, the Strait of Hormuz blockade, and U.S. President Donald Trump's visit this month to China. It will also set the agenda for the Quad Summit that has not taken place since 2024 amid India-U.S. tensions on a number of issues.

Toshimitsu Motegi

"The Quad remains a vital framework among countries that share fundamental values and strategic interests. It has delivered concrete results across a wide range of areas, including maritime security, economic security, and cybersecurity," Mr. Motegi said, but side-stepped queries on why the mechanism finds little mention in strategy documents of member countries.

He declined to respond to a specific question on whether the U.S.'s torpedoing of the Iranian ship *IRIS Dena* in the Indian Ocean on March 4 would be raised by fellow Quad members, given their agenda of ensuring peace and stability in the Indo-Pacific region.

CONTINUED ON
» PAGE 10

What is China's Hainan FTP initiative?

How has Hainan's free trade port changed tariffs and trade rules? Why is the FTP attracting new enterprises? What benefits are businesses gaining? How are the duty-free system and visa-free policy boosting tourism and consumption? What strategic role does FTP play in China's comparison with Hong Kong?

EXPLAINER

Vighnesh P. Venkitesh

The story so far:

Hainan, China's southernmost province and a tropical island in the South China Sea, has come to the forefront of the country's modern-era opening-up efforts with the beginning of its free trade port (FTP) and customs closure in December. Envisioned as a 'landmark leap' into economic ease, China is trying to set up a business hub in the island province aimed at attracting global and local customers with the appeal of zero tariffs, low personal taxes, and simplified flow of commuters and data.

What is the free trade port initiative?

The plan for the FTP in Hainan was first unveiled on June 1, 2020. The FTP was officially launched on December 18, 2025, with island-wide special customs operations implementing the policy of "freer access at the first line, regulated access at the second line, and free flow within the island". Under the initiative, tariff barriers on trade were removed from the island with the closure of ordinary customs operations, enabling easier imports. While the island remains an integral part of China, it has now become a neutral zone for international trade, with regular customs procedures and tariffs applying only to goods entering the Chinese mainland from the island. Visa-free entry for people from 86 countries is also expected to boost tourism.

Hainan will be a "new frontier of opening up, hub for regional cooperation and engine for economic globalisation," said Wang Bin, spokesperson for the Chinese Communist Party's Hainan Committee, ahead of the official opening of the FTP. He added that the FTP would help save 860 million RMB in tariffs annually while creating investment opportunities for Chinese enterprises in the Global South.

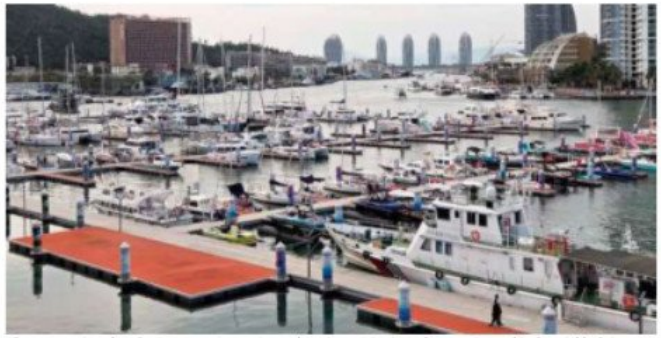

The International Yacht Centre at Sanya Central Business District, a key tourist and industrial hub in Hainan. VIGHNESH P. VENKITESH

How will the initiative help China's trade?

The island-wide special customs operation is seen as an opportunity to "deepen reforms in key sectors, steadily advance high-quality development, improve risk prevention, and build the FTP into a leading gateway for China's opening-up in the new era," He Lifeng, Chinese Vice-Premier, said at the launch of the FTP on December 18.

Since the launch, the number of tariff-free product categories has expanded from around 1,900 to 6,600, while the share of goods eligible for zero tariffs has risen from 21% to 74%. *Global Times* reported that 3,265 foreign-invested enterprises registered in the FTP between December 18 and December 31, while over 30,000 foreign trade registration enterprises were added in 2025.

According to Haikou Customs, goods worth around 753 million yuan (about $107 million) were imported into Hainan in the first few months after the FTP's opening. The value of processed and value-added goods brought into the mainland during the same period stood at around 85.9 million yuan.

How are businesses benefiting?

The establishment of the FTP has drawn numerous industries to the island. The M1 Coffee Dream Factory in Wanning is one such enterprise benefiting from the initiative. "We import coffee beans for RMB 1,100 per kilo from Panama, which cost RMB 1,700 per kilo on the mainland," said Tong Shuo, director of M1.

Hainan Ausca International Oils and Grains Co., Ltd., established with a total investment of 3.5 billion RMB, is among the first enterprises operating within the FTP. It piloted the import tariff exemption policy to produce goods with at least 30% added value after processing. The group started construction in September 2020, soon after the FTP plan was unveiled, and opened its first production line in April 2021. It now has a production line of 2 million tonnes per year.

How does the initiative encourage consumers?

The FTP has also opened Hainan to individual consumers.

Sanya, the province's main tourist hub, houses the China Duty Free centre, with a collection of global and local brands competing for customers. The CDF offers a shopping experience for both international tourists and mainland residents, provided they present a return ticket at entry. Local residents, however, face a shopping cap of 1,00,000 RMB per person per year and must travel out of the province once a year.

"The FTP is expected to bring benefits with an increase in overseas visitors, which will boost spending and help the local economy," said Bai Xue, deputy general manager at Sanya CDF. "The visa-free policy will help us provide a window to showcase Chinese culture to the world, while introducing local brands and shifting focus from the world to China," she added.

The *Global Times* reported that offshore duty-free shopping in Hainan exceeded 2 billion RMB since the FTP's opening, with more than 3,00,000 shoppers. Haikou and Sanya, the two major cities of the province, have seen the fastest growth in inbound flight ticket bookings.

What does China seek to gain with Hainan?

While Hainan is on its way to further China's strategy of economic opening up, there are multiple factors affecting its success. Unlike Hong Kong – one of the world's leading financial hubs, being a special administrative region under the Chinese government, with its own legal system, currency, and independent membership in international trade organisations – Hainan is China in all perspectives and domain.

With a customs-free, tariff-free, region outside the mainland that follows all other legal and constitutional provisions, China has made both a partner and competitor to Hong Kong in Hainan. China now has an open economic and tourist zone at the northern end of the much-contested South China Sea, with fresh and vast economic opportunities compared to congested Hong Kong.

The geopolitical and economic implications of Hainan, and its output to China, which seeks to attain "socialist modernisation" in the coming decade, will be unveiled in time.

For now, the Hainan experiment is attracting eyes and its baby strides are firm.

(The writer was in China at the invitation of the China Public Diplomacy association)

THE GIST

- Hainan has launched its free trade port (FTP) with island-wide "customs closure," enabling "freer access at the first line, regulated access at the second line, and free flow within the island," along with zero tariffs, lower taxes and simplified movement of trade, people and data.
- The FTP is attracting foreign-invested enterprises and boosting trade, tourism and consumption through expanded tariff-free products, duty-free shopping, visa-free entry for 86 countries, and growing investment and trade volumes since its launch.

‘India, Nordic countries are on the same page on peace’

While India has a different relationship with Russia, it does not mean that Nordic nations cannot engage on other points, says Iceland’s Prime Minister; the biggest growth areas in a partnership between India and Iceland will be in renewable energy, cultural cooperation and people-to-people ties, she adds, making a pitch for film crews to consider her country’s landscape as a backdrop for new projects

INTERVIEW

Kristrún Mjöll Frostadóttir

Suhasini Haidar
OSLO

India and the Nordic countries have a new engagement, driven in part by a desire for middle powers to find common ground in the face of concerns about global powers. However, there are clear differences on ties with Russia, says Iceland’s Prime Minister Kristrún Mjöll Frostadóttir. Speaking to *The Hindu* on the sidelines of the recent India-Nordic Summit in Oslo, Ms. Frostadóttir, who, at 38, is one of the world’s youngest leaders, and an economist by training, said she hopes to discuss new areas to improve bilateral trade, which is currently at extremely low levels, through a focus on renewable energy technologies. She also pitched for more Indian films to be shot against Icelandic backdrops.

Is the emergence of the relationship between India and Nordic countries driven by concerns that the three big powers right now are seen as breaking the international rule of law?

The relationship between the Nordics and India has a longer history than maybe what we’ve been seeing over the course of the last couple of years, so I don’t want to tie it directly to that, but I think, in general, a lot of countries are looking outward... Things are shifting, new deals are being done. You see this with the EU as well, you see it with Canada, and you see it now with India.

The most important message out of the [India-Nordic] summit is, there’s hope for international relations. There are still large democratic countries like India that are opening up instead of closing off, and this is what the world needs to hear.

Even so, there’s a basic difference between Nordic countries and India, over ties with Russia...

REUTERS

I won’t deny that India has a different relationship with Russia than the Nordics do. I do know, however, that Prime Minister Modi wants this war to end, and I think we’re all on that page. We believe Ukraine needs to win this war. For small Nordic countries, this is important, that you know people respect the rule of law, they respect borders, that we don’t set up double standards. We had the issue with Greenland [and the U.S.], and we want to ensure that we don’t set a precedent in that regard. That doesn’t mean that we can’t interact at other levels, but we’ve sent out clear messages on our stand on Ukraine.

India and Iceland trade relations are nascent, just about $30-40 million... Where do you see the biggest growth areas? And do you plan a visit to India?

I would love to go to India. I think that’s definitely something that we’re looking into. We should work with what we already have. We have a great relationship when it comes to renewables. There’s so much growth potential for India there with its goal of 500 gigawatts renewable energy. We also have potential in cultural ties, and [PM Modi and I] discussed the Indian film industry. We have had outside film crews coming in and using Icelandic territory as backdrop. I think that would be a very interesting cooperation that we could have.

Also, we have many people, including Indians, coming to Iceland with their skills, becoming a part of the community in a very positive way. So there’s also development opportunities there.

On that issue, when we speak to the Indian community their worry is that they are no longer welcome the way they used to be. What is the future of immigration to Europe?

I understand that [concern]. I think there’s been a big shift in attitudes to migration, especially when it comes to, I mean, I can only speak from my part of the world, where we’ve maybe been pushed into a setting where we’re focusing too much on low-skilled, low-value immigration. I don’t see that as an issue when it comes to Indian migration.

These are usually people coming in with high levels of education, going into productive jobs, so it’s also a matter of how you frame it, but this is a responsibility of the government as well.

The full interview is at newsth.live/iceland

(The reporter was in Oslo at the invitation of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to cover the India-Nordic Summit)

What did the SC say about bail under UAPA?

What are the disagreements between recent Supreme Court rulings on UAPA bail? Why is bail so difficult under Section 43D(5) of the UAPA? What did the Court say in K.A. Najeeb about prolonged incarceration and bail? What role does Article 21 play in UAPA bail jurisprudence?

Krishnadas Rajagopal

The story so far:

On May 22, the Supreme Court granted six months of interim bail to two accused in the 2020 Delhi riots case – Abdul Khalid Saifi and Tasleem Ahmad. It also referred to a larger Bench the question of whether prolonged incarceration and delay in trial can override the stringent bail curbs under anti-terror laws such as the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA). This particular law empowers the Centre to designate not only organisations but also individuals as 'terrorists'.

What concerns did the Court raise about UAPA bail rulings by smaller Benches?

A three-judge Bench in the 2021 judgment, *Union of India v. K.A. Najeeb*, had settled the principle that an undertrial cannot be made to indefinitely wait behind bars for completion of trial, however grave the offence may be.

On May 18, a Bench of Justices B.V. Nagarathna and Ujjal Bhuyan in *Syed Iftikhar Andrabi v. National Investigation Agency*, voiced serious reservations about smaller Benches "hollowing out" the principle laid down in the *Najeeb* verdict – that constitutional courts must intervene and grant bail in UAPA cases in which accused persons had spent years in pre-trial incarceration.

Justice Bhuyan, who authored the judgment, questioned the Supreme Court judgment of January 5, 2026 (*Gulfisha Fatima v. State, Government of NCT Delhi*), which denied bail to former JNU student leader Umar Khalid and his co-accused Sharjeel Imam, who were charged under the UAPA in the Delhi riots 'larger conspiracy' case. While granting five others bail, a Division Bench of Justices Aravind Kumar and N.V. Anjaria had denied the two of them relief,

The *Najeeb* verdict was the Court's response to the growing use of Section 43D(5) as a weapon in the hands of the state

Activist Umar Khalid being detained by the Delhi Police for defying prohibitory orders during the anti-CAA protests at Red Fort in New Delhi in 2019. PTI

prima facie acknowledging that they were the "alleged masterminds". Mr. Khalid had already spent over five years in jail.

Justice Bhuyan's remarks prompted the Delhi Police to raise objections before Justice Kumar, the author of the *Gulfisha Fatima* verdict, during the bail hearing of Mr. Saifi and Mr. Ahmed.

Additional Solicitor General S.V. Raju argued the *Andrabi* judgment had muddied the bail waters in UAPA cases. He rhetorically asked whether Ajmal Kasab – or Hafiz Saeed, if extradited from Pakistan – would also be entitled to bail merely because they had spent five years in prison awaiting trial.

Justice Kumar referred the question of law to a larger Bench, saying that a "perceived conflict" between two coordinate Benches (of equal strengths) of the Court did not need expressions of "serious reservation", but "resolution".

Why is bail so difficult under Section 43D(5) of the UAPA?

The section makes securing bail under the UAPA difficult. The proviso to it mandates that an accused person will not get bail if a court, on perusing the case diary or chargesheet, found "reasonable grounds" to believe that the accusations were prima facie true.

The apex court's 2019 judgment in *National Investigation Agency v. Zahoor Ahmad Shah Watali* saw a Division Bench headed by Justice A.M. Khanwilkar (now retired and currently serving as chairperson of the Lokpal) hold that an "elaborate examination" of evidence was not necessary for a court to establish prima facie guilt. The court was merely required to glance through "broad probabilities" to decide if the allegations were true, and deny bail.

Section 43D(5) turned bail jurisprudence on its head. The normal presumption of 'bail, not jail' was reversed. While ordinary bail jurisprudence was rooted in the fundamental principle that a person was innocent until proven guilty, Section 43D(5) turned the burden onto the accused, supposing the person to be guilty until found innocent.

How did the *K.A. Najeeb* judgment soften the bail bar?

The *Najeeb* verdict was the Court's response to the growing use of Section 43D(5) as a weapon in the hands of the state. For incarcerated accused persons with limited financial and legal resources, disproving terror charges becomes an uphill battle even as the prospect of trial recedes with passing years. It was in this context that the *Najeeb* judgment, authored by Justice Surya Kant (as he was then), clarified that constitutional courts could "melt down" the rigour of Section 43D(5) and grant bail to a UAPA accused who had already spent a "substantial period of time" in jail due to gross delay in trial.

The *Najeeb* verdict quoted precedents to hold that constitutional courts cannot become mute spectators before the power of Section 43D(5). They had to intervene to protect the fundamental right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution.

What did the Court clarify in the *Andrabi* verdict about Section 43D(5) and Article 21?

In the *Andrabi* judgment, Justice Bhuyan said the Court must not play ball to the Centre's argument that the gravity of offences under UAPA outweighed the human right to bail. The judge pointed out that the conviction rate under UAPA was only 2-6% across the country.

Justices Nagarathna and Bhuyan observed that an undertrial cannot be punished with denial of bail for the state's ineptitude to hold a trial on time. If the alleged offence was a serious one, it was all the more necessary for the prosecution to conclude the trial expeditiously. Bail cannot be denied solely on the ground that the charges were very serious.

The *Andrabi* judgment said the Supreme Court in *Gulfisha Fatima* case read *Najeeb* judgment wrong when it said the three-judge Bench had created an automatic entitlement to bail on account of delay. Justice Bhuyan clarified that the *Najeeb* verdict had never advanced the proposition that bail should be given in every UAPA case of prolonged incarceration. Rather, *Najeeb* case only cautioned constitutional courts against treating the statutory embargo under Section 43D(5) as the sole justification for continued detention while ignoring broader constitutional principles of personal liberty and speedy trial. It held that Section 43D(5) was subordinate to Article 21.

Did the *Gulfisha Fatima* judgment stray from the 'binding precedent' of *Najeeb* verdict?

The May 22 order, referring the question of bail in UAPA to a larger Bench, argued that the *Andrabi* judgment had misunderstood the reasoning behind the *Gulfisha Fatima* verdict. It said the judgment, which had denied bail to Mr. Khalid and Mr. Imam, had correctly applied the *Najeeb* principle. It said the *Najeeb* judgment had appreciated the strict bail regime of Section 43D(5) while advising relaxation only in cases in which there was no likelihood of completion of trial within the reasonable time and the accused had already spent a long time behind bars.

The May 22 order took pains to clarify that the *Gulfisha Fatima* judgment accepted the *Najeeb* judgment as a binding precedent. It had recognised the central place of Article 21 in the constitutional scheme and that pre-trial incarceration cannot assume the character of punishment in UAPA cases. It said that the two were denied bail on an "accused-specific evaluation" based on factors such as the evidence, their roles in the alleged conspiracy, and the need to protect the integrity of the trial.